International Journal of Applied Research 2020; 6(10): 651-654

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(10): 651-654
www.allresearchjournal.com
Received: 22-08-2020
Accepted: 28-09-2020

विनोद कुमार मिश्र
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत ।

Corresponding Author:
विनोद कुमार मिश्र
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत ।

भारत निर्माण में श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक आयाम

विनोद कुमार मिश्र

सारांश
श्रमिक किसी भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। कृषि, निर्माण कार्य, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्रमिक देश के विकास में अपना अहम् योगदान देता है। अतः भारत निर्माण में समाज की प्रगति, समृद्धि तथा खुशहाली में भारतीय श्रमिकों द्वारा किए जा रहे योगदान को नमन किया जाना चाहिए।
भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को 'भारत निर्माण योजना' की शुरूआत की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास को शामिल किया गया है। भारत निर्माण योजना का लक्ष्य गांवों को बैसाखियां न देकर उन्हें अपने हीं पैरों पर मजबूती से खड़े होने लायक बनाना है। इस योजना से ग्रामीणों को गांवों में ही जरूरत की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा होने से शहरों की ओर पलायन में कमी आती है। अब इस योजना में सम्पूर्णता की बात की गई है ताकि गांवों का सम्पूर्ण विकास हो सके। यह योजना बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। इसका सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण श्रमिकों पर पड़ा है। अतः उनके जीवन स्तर में सुधार लाने से संबंधित कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रस्तावनाः
श्रमिक देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है। किसी भी समाज, देश, संस्था, कृषि और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
श्रमिकों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना एक स्थान है। हमारे देश ने उत्पादन में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उच्च मानक हासिल किया है, वह हमारे श्रमिकों के अथक प्रयासों का नतीजा है। हमारे देश के निर्माण व विकास में बहुमूल्य भूमिका निभाने वाले लाखों मजदूरों के कठिन परिश्रम और निष्ठा का सम्मान करते हुए, उसके हितों की रक्षा के लिए सरकार एवं समाज को हमेशा तत्पर होना चाहिए।
भारत निर्माण में श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक आयाम व इस देश की समृद्धि में श्रमिकों के अथक श्रम निहित हैं। भारत में अधिकांश लोगों की जीविका का साधन एकमात्र श्रम हैं। हमारे देश में श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण वैश्वीकरण की प्रभावशीलता एवं शहरीकरण की प्रवृति में वृद्धि होना है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का एक बड़ा भाग कार्यरत है। विशेषकर नगरों में भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों की बड़ी संख्या है। हमारे श्रमिक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे– कम मजदूरी, निम्न आवास स्थल, रहन–सहन का निम्न स्तर, अनुपयुक्त भोजन, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, शिक्षा की कमी आदि। इन समस्याओं एवं कठिनाइयों से जूझने के कारण श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में स्पष्टतः गिरावट देखी जा सकती है। भारत के निर्माण क्षेत्र में जिन श्रमिकों की बहुमूल्य भूमिका है, उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति अति निम्न है। अतः इन श्रमिकों की दशा का उत्थान किए जाने की जरूरत है। सरकार श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रकार की 'सुरक्षा योजनाओं' का क्रियान्वयन कर रही है, लेकिन इन योजनाओं के चलने के बावजूद भी इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। अतः प्रशासन के साथ–साथ अनेक गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से श्रमिकों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है।
भारत निर्माण योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़क का निर्माण करना और ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ना है। सड़कों की सुविधाओं में सुधार करना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना इसी का हिस्सा है। भारत निर्माण योजना का एक और मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करना है ताकि ग्रामीणों को 'घर' मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लाखों घरों का निर्माण कराया जाता

है। ग्रामीण भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वारा सभी गांवों को बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। भारत निर्माण योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक गांव को दूरसंचार के माध्यम से जोड़ना चाहती है।

अब इस योजना में किसी खास क्षेत्र की बात से हटकर सम्पूर्णता की बात की गई है। सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास की बात की गयी है ताकि गांवों का सम्पूर्ण विकास हो सके।

साहित्य समीक्षा

विषय से संबंधित साहित्य समीक्षा के द्वारा इस क्षेत्र को समझना आसान हो जाता है। साहित्य पुनरावलोकन हमारे शोध की सीमा का निर्धारण करता है, साथ ही साथ मार्गदर्शक की भूमिका में आकर विशेष एवं भिन्न अध्ययन के लिए शोधकर्ता को प्रेरित करता है। भारत गांवों का देश है। भारत निर्माण शब्द से हमारे जेहन में जो चित्र उभरता है, वह है 'गांव'। गांव शब्द आते ही हमारे दिमाग में ग्रामीण क्षेत्र की पूरी तस्वीर उभरती है। जैसे– मूलभूत सुविधाओं का अभाव, भौतिक सुख–सुविधाओं से वंचित क्षेत्र, कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय, श्रमिक, श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव, महिलाओं की निम्न स्थिति व लैंगिक असमानता, खेतों में काम करती हुई महिला, कामगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, शिक्षा, सड़क, बिजली का अभाव एवं निर्माण कार्य में सरकार की कई योजनाएं जो वहां की आर्थिक–सामाजिक बुनियाद को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करती हुई दृष्टिगत होती है।

मयंक श्रीवास्तव का अध्ययन, यह तथ्य प्रस्तुत करता है कि भारत निर्माण में आधारभूत संरचनाओं का अभाव, विकास की परिकल्पना को कमजोर करता है। इन्होंने आधारभूत संरचनाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा है– सामाजिक आधारभूत संरचनाएं– स्वास्थ्य, आवास, पेयजल एवं शिक्षा इत्यादि।

आर्थिक आधारभूत संरचनाएं – सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, सूचना और बैंकिंग इत्यादि। ग्रामीण अवसंरचना निर्माण व योजनाओं को वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। अतएव तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता को बेहतर निगरानी और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए सक्षम बनाना होगा। डा. कल्पना द्विवेदी के अध्ययन का निचोड़ यह बताता है कि गांवों के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने के लिए ऐसी बुनियादी सुविधाएं शामिल करने की कोशिश की गई है कि वे उस नींव पर स्वयं का विकास कर सके। भारत निर्माण दीर्घकालीन एवं व्यावहारिक योजना है। भारत निर्माण के तहत गांवों का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल है। भारत निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संरचना के विकास के लिए है। श्रमिकों, बेरोजगारों एवं निर्धन ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक जीवन को उन्नत करने के लिए तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम की व्यूह रचना की गई। अमरजीत सिन्हा ने ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण पर कार्य किया है। इनका कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतर सड़क संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। इससे बाजार तक लोगों की पहुंच बनती है। श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। कृष्ण चन्द्र चौधरी का अध्ययन भारत निर्माण पर है। भारत निर्माण में महिलाओं के श्रमबल को जोड़ने की जरूरत है। उनका अध्ययन यह कहता है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त महिला असमानता की खाई पाटने की जरूरत है। इसप्रकार विषय से संबंधित साहित्यों ने शोध कार्य का मार्गदर्शन किया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. श्रमिक परिवारों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. 'भारत निर्माण योजना' से संबंधित सूचनादाताओं के विचार जानना अध्ययन का उद्देश्य है।
3. भारत निर्माण योजना के उद्देश्यों की सफलता एवं असफलता का पता लगाना।
4. श्रमिकों का पलायन आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त खोखलेपन को स्पष्ट करता है। इस संदर्भ में वास्तविक तथ्यों से रू–बरू होना है।
5. कार्य क्षेत्र में लैंगिक असमानता की समस्या का अध्ययन करना शोध का विषय है।
6. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित उत्तरदाताओं की जानकारी के संबंध में पता करना।

अध्ययन क्षेत्र या समग्रः

शोध का अध्ययन क्षेत्र सारण जिला है। शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्यों पर आधारित है।

अध्ययन विधि :

(i) **समग्र एवं निदर्शन** : निदर्शन किसी भी अनुसंधान कार्य की आधारशिला होती है। यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी, अनुसंधान के परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे। निदर्शन समग्र अथवा जनसंख्या के किसी एक अंश को उस समय के प्रतिनिधि के रूप में लेना है। वर्तमान अध्ययन में 50 शहरी एवं ग्रामीण उत्तरदाताओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर चयन कर अध्ययन पूर्ण किया जायेगा।

(ii) **तथ्य संकलन के स्रोत :** प्राथमिक एवं द्वैतीयक

(iii) **तथ्य संकलन की प्रविधियाँ**

(A) **साक्षात्कार अनुसूची** : "भारत निर्माण में श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक आयाम के सन्दर्भ में आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक साक्षात्कार अनुसूचि का निर्माण किया गया है।

(B) **आंकड़ा संग्रह की तकनीक एवं विश्लेषण** : साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन आंकड़ा संग्रह के प्रमुख श्रोत होंगे।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण विभिन्न सारणियों के माध्यम से रखा जा रहा है।

सारणी संख्या–1: उत्तरदाताओं की वैयक्तिक तथा सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का परिदृश्य

क्र.स.	चर	सवर्ण	प्रतिशत	पिछड़ी जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	जाति	06	12.0	22	44.0	22	44.00	50	100.0
2	लिंग	पुरूष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत				
		44	88.0	6	12.0			50	100.0
3	आयु	25 से कम	प्रतिशत	25–40	प्रतिशत	40–50	50 से उपर		
		18	36.0	20	40.0	9 (18.0)	3 (6.0)	50	100.0
4	धर्म	हिन्दू	प्रतिशत	मुस्लिम	प्रतिशत				
		44	88.0	06	12.0			50	100.0
5	आय	निम्न	मध्यम	उच्च मध्यम	उच्च				
		25 (50.0)	15 (30.0)	6(12.0)	4 (8.0)			50	100.0
6	शिक्षा	अशिक्षित	प्रतिशत	शिक्षित	प्रतिशत				
		14	28.0	36	72.0			50	100.0

7	वैवाहिक	अविवाहित	प्रतिशत	विवाहित	प्रतिशत				
		18	36.0	32	64.0			50	100.0
8.	व्यवसाय	कृषि	नौकरी पेशा	उद्योग	अन्य				
		15 (30)	20 (40)	10 (20)	5 (10)			50	100.0

उपरोक्त सारणी संख्या 1 के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन के लिए चुने गए कुल 50 प्रवासियों में से 12 प्रतिशत सवर्ण जाति, 44 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 44 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि अन्य जातियों की तुलना में पिछड़ी जातियों में प्रवसन दर अधिक हैं। 88 प्रतिशत पुरूष और 12 प्रतिशत स्त्री हैं। इससे स्पष्ट है कि पुरूषों में प्रवसन की गति महिलाओं की तुलना में तीव्र है। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 25 से कम 36 प्रतिशत, 25–40 के मध्य 40 प्रतिशत, 40–50 के बीच 18 प्रतिशत एवं 50 से उपर 6 प्रतिशत लोग हैं जिनका पलायन गांव से शहर की ओर हुआ है। 88 प्रतिशत हिन्दू और 12 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। स्पष्ट है कि हिन्दुओं में सर्वाधिक पलायन हुआ है। आय से सम्बन्धित प्रवासियों का विश्लेषण क्रमशः निम्न–50.00 प्रतिशत, मध्यम–30 प्रतिशत, उच्च मध्यम 12.00 प्रतिशत एवं उच्च–8.00 प्रतिशत है। इनके शैक्षणिक स्तर की जांच की गई है। 28 प्रतिशत अशिक्षित एवं 72 प्रतिशत शिक्षित हैं। वैवाहिक स्तर का अवलोकन किया गया है, 36 प्रतिशत अविवाहित एवं 64 प्रतिशत विवाहित हैं अर्थात् प्रवासियों में विवाहितों की संख्या ज्यादा है। व्यवसाय के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कृषि–30 प्रतिशत, नौकरी पेशा 40 प्रतिशत, उद्योग–20.00 प्रतिशत एवं 10.00 प्रतिशत अन्य व्यवसाय करने वालों में प्रवसन अधिक हो रहा है।

सारणी संख्या–2: जनसहभागिता का अभाव कार्यक्रमों की सफलता में बाधक है एवं उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति एवं जाति

क्र.सं.	जाति समूह	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कह नहीं सकते	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सवर्ण जाति	06	100.0	ग	ग	ग	ग	06	12.00
2	पिछड़ी जाति	12	24.00	06	12.00	04	8.00	22	44.00
3	अनुसूचित जाति	05	22.75	12	54.54	05	22.72	22	44.00
	कुल योग	23	46.00	18	36.00	09	18.00	50	100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 02 में जाति के आधार पर पूछा गया कि क्या जनसहभागिता का अभाव कार्यक्रमों की सफलता में बाधक है? सवर्ण, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं ने क्रमशः 100:, 24:, एवं 22.75: ने हाँ में अपना जवाब व विचार रखा है जबकि इन्हीं जातियों के क्रमशः 12:, एवं 54.54: ने अपना जवाब 'ना' में दिया है। 18:ए उत्तरदाताओं ने कह नहीं सकते, ऐसा कहा है। अर्थात् 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि जनसहभागिता का अभाव कार्यक्रमों की सफलता में बाधक है।

सारणी संख्या–3: सड़क, विद्युतीकरण एवं आवास निर्माण से श्रमिकों की बेरोजगारी दूर हुई है।

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	24	48.00
नहीं	23	46.00
कह नहीं सकते	03	06.00
कुल योग	50	100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या–03 में पूछे गए प्रश्न कि क्या सड़क, विद्युतीकरण एवं आवास निर्माण से श्रमिकों की बेरोजगारी दूर हुई है? 48.00 प्रतिशत ने कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है जबकि 46.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी राय विपक्ष में दी है तथा 6.00 प्रतिशत ने प्रश्न के जवाब में रूचि नहीं दिखाई है। अतएव इस सारणी से स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी दूर होने के संबंध में लगभग पक्ष–विपक्ष की राय आधी–आधी भागों में बंटी हुई है। अतएव यह कहा जा सकता है कि भारत निर्माण योजना बेरोजगारी दूर करने में पूरी तरह सफल नहीं है, लेकिन पूरी तरह इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। यदि बेरोजगारी दूर हो जाती तो श्रमिकों का प्रवसन नहीं होता।

सारणी संख्या–4: गाँवों से नगर की ओर श्रमिकों का पलायन हो रहा है।

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	27	54.00
नहीं	21	42.00
कह नहीं सकते	02	4.00
कुल योग	50	100.00

इस प्रश्न के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि क्या गांवों से नगर की ओर श्रमिकों का पलायन हो रहा है? सारणी संख्या–04 में पलायन से सम्बन्धित सवाल पर 54.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कथन के पक्ष में 'हाँ' कहा है जबकि 42.00 प्रतिशत ने 'नहीं' कहा तथा 4.00 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया है।

गांवों में जब काम नहीं होता है या जब खेती का सीजन नहीं रहता है या बेहतर सुविधा लाभ लेने के लिए अमूमन कृषक मजदूर शहर की ओर पलायन करते हैं। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। यहां काम और व्यवसाय का अभाव है। आजीविका के कम अवसर हैं। यही वजह है कि श्रमिक शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

सारणी संख्या–5: महिला कामगारों के साथ कार्यक्षेत्र में भेदभाव किया जाता है।

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	33	66.00
नहीं	15	30.00
कह नहीं सकते	02	04.00
कुल योग	50	100.00

प्रस्तुत तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 66.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि महिला कामगारों के साथ कार्यक्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। लैंगिक असमानता की समस्या है। 30.00 प्रतिशत ने कहा कि ऐसा नहीं है तथा 4.00 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि काम के क्षेत्र में महिला होने के कारण पुरूषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है एवं आर्थिक क्षेत्रों में लैंगिक विषमता की समस्या से महिलाएं जूझ रही हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण श्रमिकों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव है। योजनाओं का लाभ जरूरतमन्द व्यक्ति तक नहीं पहुंचने से विकास को सही दिशा नहीं मिल पाती है। भ्रष्टाचार विद्यमान होने से निर्माण सही मायने में सफल नहीं हो पाया है। भारत निर्माण के लक्ष्यों तक पहुंचने में प्रशासनिक एवं राजनीतिक नकारात्मक हस्तक्षेप बाधक है। शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है। जातिवाद सामाजिक–आर्थिक विकास की राह में बाधक है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास आवश्यक है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा आर्थिक निर्भरता से ही संभव है। हमने यह महसूस किया कि जिन ग्रामीण इलाकों का सम्पर्क पक्की सड़कों से है वहां आमदनी एवं साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अन्त में यह कहना आवश्यक है कि भारत निर्माण में मानवीय पहलुओं की अपेक्षा केवल निर्माण कार्यों को हीं विकास माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथों की सूची :

1. सौरभ कुमार, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की वर्तमान स्थिति, कुरूक्षेत्र, मार्च 2014
2. डा. कल्पना द्विवेदी, भारत निर्माण योजना की भूमिका, कुरूक्षेत्र, मार्च 2014
3. अमरजीत सिन्हा, योजना, अक्टूबर, 2017
4. कृष्णचन्द्र चौधरी, योजना, अक्टूबर, 2017
5. पाण्डेय, प्रेम नारायण 2000: ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
6. तिवारी, अवधेश 2012, ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रथम संस्करण, जवाहर नगर, नई दिल्ली
7. Goode & Hatt, Methods in Social Research.
8. Lundberg, Social Research.
9. भारत 2019 प्रकाशन विभाग